देती हैं और वे कृत्रिम इन्सुलिन पर अपना जीवनयापन करते हैं। साधन-सम्पन्न परिवार के बच्चे इन्सुलिन के महंगे खर्च और समय-समय पर ग्लूकोज़ की जांच पर होने वाले महंगे खर्च को वहन कर सकते हैं, परन्तु जनसामान्य परिवार के बच्चों के लिए यह खर्च बहुत भारी हो जाता है। अधिकांश बच्चे अज्ञानतावश टाइप-1 डायबिटीज़ की जांच के अभाव में जीवन-लीला से भी हाथ धो बैठते हैं। अभी तक टाइप-1 डायबिटीज़ के परीक्षण की भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूलों में भी इस तरह की जांच की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

सामान्यतः बाह्य रूप से शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे विकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन बचपन से ही जिन बच्चों की पैंक्रियाज़ काम करना बंद कर देती हैं, उन्हें विकलांगता की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, जबकि वह भी तो एक मानव अंग है। इससे इन बच्चों को किसी भी प्रकार की शासकीय सहायता नहीं मिल पाती है, न ही इन्हें नौकरी इत्यादि में कोई प्राथमिकता मिलती है। इलाज के लिए होने वाले खर्च में भी किसी प्रकार की सरकारी सहायता पीड़ित बच्चों को नहीं मिलती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को संज्ञान में लाकर मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार टाइप-1 डायबिटीज़ पीड़ित बच्चों को विकलांगता की श्रेणी में रखकर विशेष अनुदान इत्यादि देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

MR. CHAIRMAN: Shri M. Shanmugam.

Demand for consultation with trade unions before notifying rules/regulations in Labour Codes

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, there is a time-tested long tradition in the labour world that whenever new legislations or rules are framed, trade union leaders are always consulted through bipartisan meetings. The labour community is already launching agitations and *dharnas* for notifying rules and regulations which are against the interest of labour.

I would, therefore, through this House, urge upon the hon. Prime Minister and the hon. Labour Minister to call a meeting of all the recognised trade unions before finalizing the draft rules on various Labour Codes like the Code on Industrial Relations, the Code on Occupational Safety and Health and the Code on Social Security. I demand that rules should be notified only after consulting all the labour union leaders and getting a consensus.

MR. CHAIRMAN: Instead of saying 'following matter', you should say 'Consultation with trade unions before notifying rules and regulations.' You have to read the heading. Shri Ram Nath Thakur.